बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 73 ● नई दिल्ली ● शनिवार 27 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

लाल किला विस्फोट मामला: अदालत ने बढ़ाई दो आरोपियों की एनआईए हिरासत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ा दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से दस और दिनों तक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ की जाएगी। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही को कवर करने से रोक दिया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच के अनुसार, उमर-उन-नबी 10 नवंबर को विस्फोटक से भरी कार चला रहा था और वह इस आतंकवादी हमले का केंद्रित षड्यंत्रकारी था।

वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, साहिबजादों ने धार्मिक कट्टरता-आतंकवाद को जड़ से मिटाया

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीर साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए, क्रूर मुगल सल्तनत के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े होकर धार्मिक कट्टरता और आतंक के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंकने के उनके साहस और वीरता की सराहना की। वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादों ने, जिन्हें बहुत कम उम्र में मुगल साम्राज्य का सामना करना पड़ा, अत्याचार के विरुद्ध अपने संघर्ष में सभी परिस्थितियों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र वीर बाल दिवस मना रहा है। आज हम उन वीर साहिबजादों को याद करते हैं जो भारत का गौरव हैं। वे भारत के अदम्य साहस, वीरता और साहस की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उन वीर साहिबजादों ने उम्र और परिस्थितियों की सीमाओं को तोड़ दिया। वे क्रूर मुगल सल्तनत के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़े रहे और धार्मिक कट्टरता और आतंक के अस्तित्व को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसे गौरवशाली अतीत वाला राष्ट्र कुछ भी हासिल कर सकता है। 26 दिसंबर, 1704 को, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वज़ीर खान के आदेश पर, सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में इस्लाम धर्म अपनाने का विरोध करने के कारण, जिंदा ईंटों में चुनवा दिया गया था। उनके दो बड़े पुत्रों, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। वीर बाल दिवस के महत्व

को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को मुगलों के विरुद्ध खड़े होने के वीर साहिबजादों के उद्देश्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस गहरी भावना और श्रद्धा का दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को बहुत कम उम्र में ही अपने समय की सबसे शक्तिशाली सत्ता का सामना करना पड़ा था। वह लड़ाई भारत के मूलभूत आदर्शों और धार्मिक कट्टरता के बीच थी। यह सत्य और असत्य की लड़ाई थी। उन्होंने आगे कहा कि उस युद्ध के एक तरफ दसवें गुरु, श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, और दूसरी तरफ औरंगजेब का क्रूर शासन था। हमारे साहिबजादे उस समय युवा थे, लेकिन औरंगजेब और उसकी क्रूरता उनकी उम्र को नहीं समझती थी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि औरंगजेब की क्रूरता के बावजूद, उसके सेनापति उन चार साहिबजादों में से एक को भी नहीं डिगा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लेकिन औरंगजेब और उसके सैन्य कमांडर यह भूल गए थे कि हमारे गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे तपस्या और त्याग की साक्षात मूर्ति थे। वीर साहिबजादों को उनसे यह विरासत मिली थी, इसलिए भले ही पूरा मुगल साम्राज्य उनके विरुद्ध खड़ा था, वे उन चार साहिबजादों में से एक को भी नहीं हिला सके। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि वीर बाल दिवस मनाने की उनकी पहल ने साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जब भी 26 दिसंबर आता है, मुझे यह जानकर संतोष होता है कि हमने साहिबजादों (गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों) की वीरता से प्रेरित होकर वीर बाल दिवस मनाना शुरू कर दिया है। पिछले चार वर्षों में, वीर बाल दिवस की इस नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणादायक कहानियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल, देश के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, अब 13 राजस्व जिले, एक जैसी होंगी सभी सीमाएं

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक नक्शे को नए सिरे से गढ़ते हुए 13 राजस्व जिलों की व्यवस्था लागू कर दी है. इससे राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की सीमाएं एक समान हो गई हैं, जो अब तक प्रशासनिक कामकाज में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थीं. सरकार का दावा है कि इस फैसले से शासन अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनता के करीब होगा. राजस्व जिलों और नगर निगम जोन की अलग-अलग सीमाओं के कारण अधिकारियों और आम नागरिकों दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब सीमाएं एक जैसी होने से अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम खत्म होगा और फाइलों के चक्कर भी कम होंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समस्या दशकों से लंबित थी, जिसे उनकी सरकार ने केवल 10 महीनों में सुलझा दिया.

जून में हुई थी घोषणा, दिसंबर में मिली मंजूरी

भाजपा सरकार ने जून महीने में 11 नगर निगम जोन की जगह 13 राजस्व जिले बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद इस प्रस्ताव पर लगातार काम चलता रहा. 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाकर इसे अंतिम मंजूरी दी. उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सहमति के बाद अब इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

हर जिले में बनेगा मिनी

सचिवालय

नई व्यवस्था के तहत सरकार हर जिले में मिनी सचिवालय स्थापित करने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है. इन मिनी सचिवालयों में एक ही छत के नीचे जनता से जुड़े सभी प्रमुख सरकारी काम होंगे. इसका उद्देश्य नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर से राहत देना और सेवाओं की डिलीवरी को तेज करना है.

बजट और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

नए जिलों के गठन को लागू करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में शुरुआती तौर पर 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. सरकार का मानना है कि यह निवेश प्रशासनिक सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में इसका लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा.

एसडीएम की संख्या बढ़ी, काम का बंटवारा साफ

जिलों की संख्या बढ़ने के साथ ही उपजिलाधिकारियों यानी एसडीएम की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है.

नई दिल्ली और मध्य जिला में दो-दो एसडीएम होंगे. दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी जिलों में चार-चार एसडीएम तैनात किए जाएंगे. बाकी सभी जिलों में तीन-तीन एसडीएम कार्यभार संभालेंगे. सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में ही कार्यालय से काम करेंगे.

आम जनता को होंगे ये फायदे

इस बदलाव से सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी. प्रशासन आम नागरिकों के और करीब आएगा. अधिकारियों पर काम का दबाव संतुलित होगा और सीमाओं को लेकर असमंजस खत्म होगा. लोगों को यह स्पष्ट रहेगा कि वे किस प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं, जिससे शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सकेगा. राजस्व विभाग, नगर निगम और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर होगा. शहरी योजना, आपदा प्रबंधन और भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन भी अधिक प्रभावी बनेगा.

13 जिले और उनके एसडीएम कार्यालय

* दक्षिणी पूर्वी - जंगपुरा, कालकाजी, बदरपुर
* पुरानी दिल्ली - सदर बाजार एवं चांदनी चौक
* उत्तरी - बुराड़ी, आदर्शनगर, बादली
* नई दिल्ली - दिल्ली कैंट एवं नई दिल्ली
* मध्य जिला - पटेल नगर एवं करोलबाग
* मध्य उत्तरी - शकूर बस्ती, शालीमारबाग एवं मॉडल टाउन
* दक्षिणी पश्चिमी - नजफगढ़, मटियाला, द्वारका एवं बिजवासन
* बाहरी उत्तरी - मुंडका, नरेला, बवाना
* उत्तरी पश्चिमी - किराड़ी, नांगलोई जाट एवं रोहिणी
* उत्तरी पूर्वी - करावल नगर, गोकलपुरी, यमुना विहार एवं शाहदरा
* पूर्वी जिला - गांधीनगर, विश्वास नगर एवं पटपड़गंज
* दक्षिणी - छतरपुर, मालवीय नगर, देवली एवं मेहरौली

दिल्ली मेट्रो होगी अपग्रेड, जल्द ही जोड़े जाएंगे लग्जरी कोच

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अब मेट्रो सेवा को नए अंदाज में अपग्रेड करने की तैयारी है.

केंद्र सरकार ने मेट्रो को यादा आरामदायक और आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटाई जा सके. दिल्ली मेट्रो की छह बोगियों वाली ट्रेनों में जल्द ही लग्जरी कोच जोड़े जाएंगे.

इन कोचों में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑफिस कैबिन जैसी आरामदायक सीटिंग का अनुभव मिलेगा. हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को सामान्य किराए से अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शुल्क की राशि फिलहाल तय नहीं की गई है. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त आय का उपयोग मेट्रो में आम यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने में किया जाएगा.

प्रदूषण और ट्रैफिक घटाने की दोहरी कोशिश

केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर के नेहरू नगर में आयोजित जनसभा के दौरान इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मेट्रो को अधिक सुविधाजनक बनाने से लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित होंगे. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी, धुएं में कमी आएगी और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आसान होगा.

मेट्रो की भूमिका और विस्तार की रफ्तार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का रोजाना करीब 35 लाख लोग उपयोग करते हैं और प्रतिदिन लगभग 65 लाख यात्राएं होती हैं. उन्होंने कहा कि यदि मेट्रो जैसी सुविधा न होती तो आज दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कहीं यादा गंभीर होती. उनके अनुसार राजधानी पिछले दो दशकों से कई शहरी समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें सड़क, परिवहन और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियां शामिल हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए शहरी विकास मंत्रालय हर महीने दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर रहा है।

मेट्रो नेटवर्क में भारत की वैश्विक छलांग

वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में 400 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है. सरकार का दावा है कि जल्द ही एक ही स्थान पर सबसे लंबी मेट्रो लाइनों के मामले में दिल्ली शिकागो को पीछे छोड़ देगी. देशभर में कुल 1100 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, जबकि 800 किलोमीटर का निर्माण कार्य जारी है.

इनमें से 400 किलोमीटर लाइन पूरी होते ही भारत एक ही देश में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा.

वीर बाल दिवस पर बंगला साहिब में नतमस्तक हुए बीजेपी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी पहुंचे

नई दिल्ली । वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर माथा टेका. इस दौरान उन्होंने दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की महान शहादत को नमन किया. मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की कुर्बानी पूरे देश के लिए प्रेरणा है. उन्होंने बताया कि दो बड़े साहिबजादे युद्धभूमि में शहीद हुए, जबकि दो छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया. इसी बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल सिख समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है. सिरसा ने जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस के मौके पर एक बड़े समागम को संबोधित करेंगे. दिल्ली सरकार समेत देश की कई राय सरकारें इस दिन साहिबजादों को समर्पित कार्यक्रम आयोजित कर रही

हैं. इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की. दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण पर बात करते हुए पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम फिर खराब हो सकता है. उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से धुंध और कोहरा बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग के पुराने आंकड़ों के मुताबिक भी इस दौरान प्रदूषण बढ़ता है. उन्होंने कहा कि भले ही ग्रैप-4 हटा लिया गया हो, लेकिन जनता को सतर्क रहना जरूरी है. बिना पीयूसीसी वाली गाड़ियां सड़क पर न निकालें, बिना जरूरत वाहन का इस्तेमाल न करें और कूड़ा या लकड़ी जलाने से बचें, क्योंकि इससे बायोमास बर्निंग बढ़ती है और प्रदूषण और गंभीर हो जाता है. बीएस-6 से नीचे की गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश को लेकर सिरसा ने कहा कि अगर लोग ऐसी गाड़ियां न लाएं तो यह बेहतर होगा, हालांकि फिलहाल उनके आने पर पूरी तरह रोक नहीं है. उन्होंने अपील की कि लोग खुद जिम्मेदारी दिखाएं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दर्ज FIR को लेकर कहा कि किसी भी धर्म के प्रतीकों का मजाक उड़ाना या धार्मिक भावनाएं भड़काना गलत है. उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा जरूरी है और ऐसी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है. दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है और कानून अपना रास्ता तय करेगा. बांग्लादेश में हिंदू की हत्या को लेकर सिरसा ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि मानवता और धर्म की हत्या है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कट्टरवाद को बढ़ावा देती हैं और इससे पीड़ा और बढ़ जाती है. उन्होंने दुख जताया कि इस मामले पर कई कट्टरपंथी संगठनों ने चुप्पी साध रखी है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

कुलदीप सेंगर की जमानत पर बवाल, महिलाएं बोलीं- यह अन्याय है, न्याय चाहिए

नई दिल्ली । उन्नाव बलात्कार मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर शुक्रवार को लोगों ने अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अदालत परिसर के पास जमा हुए और जमानत आदेश के विरोध में नारे लगाते हुए अपनी आवाज उठाईं। ये विरोध प्रदर्शन उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार द्वारा सेंगर की जेल की सजा को निलंबित किए जाने पर व्यक्त की गई गंभीर चिंताओं के बीच हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं, ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सेंगर की सजा निलंबित करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए नारे लगाए। पुलिस कर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया था क्योंकि इलाके में कानून के तहत प्रतिबंध लागू थे। सभा को संबोधित करते हुए महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा वर्णित घोर अन्याय के खिलाफ एक शांतिपूर्ण अपील है। उन्होंने कहा कि आज हम उच्च न्यायालय में शांतिपूर्वक अपील करने आए हैं कि हमारी बेटी के साथ हुए अन्याय को रद्द किया जाए और हमारी याचिका पर सुनवाई की जाए। अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हम विरोध करेंगे और यह हमारा अधिकार है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी इस आदेश की आलोचना करते हुए इसे एक खतरनाक मिसाल बताया। उन्होंने कहा, यह एक बड़ा झटका है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने एक तकनीकी खामी के आधार पर सेंगर को छूट दी है, उससे

न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे देश की महिलाओं का विश्वास हिल जाएगा। पीड़िता की मां ने भावुक होकर जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, उनकी जमानत याचिका खारिज होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें हाई कोर्ट पर से भरोसा उठ गया है। अगर हमें वहां न्याय नहीं मिला, तो हम दूसरे देश चले जाएंगे। उन्होंने अपने पति की हिरासत में हुई मौत के मामले में कड़ी सजा की भी मांग की। हाल ही में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। सेंगर को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी है, जहां उनकी अपील फिलहाल लंबित है।

भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या आम भारतीय परिवार भी उसी गति से आगे बढ़ पा रहें

वैश्विक स्तरपर भारत आज जब देश वैश्विक मंचों पर आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व और कूटनीतिक प्रभाव की बात कर रहा है, उसी समय करोड़ों परिवारों के सामने एक साझा चिंता खड़ी है,बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होगी,बीमारी आने पर इलाज कैसे होगा और कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कैसे निपटा जाएगा? यही तीन प्रश्न आज भारत की सामाजिक सच्चाई औरनीति-निर्माण की कसौटी बन चुके हैं।भारत इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में जिस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, वहां आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ एक बड़ा प्रश्न लगातार उभर रहा है,क्या यह विकास आम नागरिक के जीवन को वास्तव में सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक बना पा रहा है मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन उसके सकल घरेलू उत्पाद या वैश्विक रैंकिंग से नहीं,बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि वहां का एक साधारण परिवार कितनी सहजता से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच पा रहा है। भारत में आज सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज केवल नीतिगत मुद्दे नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के अस्तित्व भविष्य और सामाजिक स्थिरता से जुड़े जीवन-मरण के प्रश्न बन चुके हैं।अभी दो दिन पूर्व आरएसएस के सरसंघ चालक ने भी एक कार्यक्रम में कहा सस्ती शिक्षा व इलाज हर व्यक्ति की जरूरत है,कैंसर मरीज के अलावा उसके परिवार पर भी भयंकर त्रासदी लाता है।सभ्य समाज की आधारशिला - संयुक्त राष्ट्र,विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बार-बार स्वीकार किया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की मानव पूंजी का मूल स्तंभ होते हैं।शिक्षा व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समाज में योगदान करने की क्षमता देती है, जबकि स्वास्थ्य उसे उस क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाता है। यदि इनमें से कोई एक भी कमजोर हो, तो विकास की पूरी संरचना असंतुलित हो जाती है। भारत में समस्या यह नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियां नहीं हैं, बल्कि यह है कि उनकी लागत आम नागरिक की आय से कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारत की स्थिति यह है कि फिनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे जैसे देशों में शिक्षा को सार्वजनिक निवेश के रूप में देखा जाता है,जहां उच्च शिक्षा तक लगभग निःशुल्क पहुंच उपलब्ध है।इसके विपरीत भारत में सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और संख्या मांग के अनुपात में कम है, जिससे निजी क्षेत्र को अत्यधिक विस्तार का अवसर मिला। यह स्थिति सामाजिक असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि प्रतिभा के बजाय आर्थिक क्षमता शिक्षा के अवसर तय करने लगती है।यह जानकारी मीडिया के संज्ञान से दी गई है। साथियों बात अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य विकास नहीं जीवन का प्रश्न है, इसको समझने की करें तो, किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सेवाएं नहीं होतीं,वे नागरिक की गरिमा, अवसर और भविष्य की गारंटी होती हैं। भारत में सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज अब केवल मध्यम वर्ग की मांग नहीं रहे, बल्कि गरीब, निम्न-मध्यम और यहां तक कि स्थिर आय वाले परिवारों के लिए भी जीवन की प्राथमिक जरूरत बन चुके हैं।एक बच्चा यदि पढ़ नहीं पाता, तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है। और यदि कोई बीमार पड़ जाए, तो पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में डूब जाता है।महंगी होती शिक्षा- सपनों पर भारी फीस-भारत में शिक्षा को संविधान ने मौलिक अधिकार माना, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अच्छी शिक्षा अब क्षमता से अधिक खर्च मांग रही है।निजी स्कूलों की फीस, किताबें, कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाएं,इन सबने मिलकर शिक्षा को एक दीर्घकालिक आर्थिक दबाव में बदल दिया है।आज एक औसत परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। यह स्थिति केवल परिवार की बचत नहीं, बल्कि समाज की समानता को भी कमजोर करती है। साथियों बात अगर हम स्वास्थ्य सेवा-इलाज या आर्थिक तबाही? इसको समझने की करें तो,भारत में बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि आर्थिक आपदा बन चुकी है।विश्व स्वास्थ्य संगठनों के अनुसार, इलाज पर होने वाला अधिकांश खर्च सीधे परिवार की जेब से जाता है। इसका अर्थ है,एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को वर्षों पीछे धकेल सकती है।सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी पहुंच, क्षमता और भरोसे को लेकर अब भी बड़े सवाल बने हुए हैं।कैंसर- एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को लड़ाई-कैंसर आज भारत में तेजी से बढ़ती बीमारी बन चुका है। बदलती जीवनशैली, प्रदूषण, तंबाकू, तनाव और देर से जांच,इन सबने मिलकर कैंसर को राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है।कैंसर का इलाज लंबा, महंगा और मानसिक रूप से थकाने वाला होता है। कई बार परिवार का कमाने वाला सदस्य बीमार पड़ता है और दूसरा सदस्य देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देता है।इस तरह कैंसर एक व्यक्ति की बीमारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का संघर्ष बन जाता है।रोकथाम ही सबसे सस्ता इलाज-अंतरराष्ट्रीय अनुभव साफ बताते हैं,कैंसर की रोकथाम और समय पर जांच इलाज से कहीं अधिक प्रभावी और सस्ती है। नियमितस्क्रीनिंग, जन-जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मजबूती और जीवनशैली में सुधार से कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत को अब इलाज-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर रोकथाम-केंद्रित स्वास्थ्य नीति अपनानी होगी।भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च दुनिया के कई देशों की तुलना में जेब से सीधे अधिक है। एक गंभीर बीमारी अक्सर केवल रोगी को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से बीमार कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में हर साल लाखों लोग केवल इलाज के खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह तथ्य अपने- आप में बताता है कि सस्ता इलाज केवल स्वास्थ्य नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है।कैंसर, एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक संकट है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है।

शहरीकरण, प्रदूषण, असंतुलित आहार, तंबाकू सेवन,तनावपूर्ण जीवन शैली और देर से निदान,ये सभी मिलकर कैंसर को एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कैंसर का असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता; यह परिवार की मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता है।कैंसर इलाज की लागत और परिवार पर प्रभावभारत में कैंसर का इलाज अत्यंत महंगा है।कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी की लागत कई परिवारों की सालों की आय के बराबर होती है। इलाज के दौरान परिवार का कोई सदस्य अक्सर काम छोड़ने को मजबूर होता है, जिससे आय और घट जाती है।

इस प्रकार कैंसर एक व्यक्ति की बीमारी न रहकर पूरे परिवार की भयंकर सामूहिक त्रासदी बन जाता है। साथियों बात अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य का सीधा सम्बंध इसको समझने की करें तो,भारत में सस्ती शिक्षा- सपना या सुलभ अधिकार?स्वतंत्रता के समय भारत ने शिक्षा को सामाजिक न्याय का माध्यम माना था। संविधान के अनुच्छेद 21-ए ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया,किंतु व्यावहारिक स्तरपर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा लगातार महंगी होती चली गई। निजी स्कूलों और कॉलेजों की बढ़ती फीस, कोचिंग संस्कृति, और प्रतियोगी परीक्षाओं की लागत ने शिक्षा को एक आर्थिक बोझ में बदल दिया है। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना कई बार जीवन की सारी बचत और कर्ज पर निर्भर हो जाता है। शिक्षित समाज अधिक स्वास्थ्य- जागरूक होता है।स्वस्थ नागरिक बेहतर शिक्षा और उत्पादकता में योगदान देता है।और जब बीमारी का बोझ कम होता है, तो परिवार शिक्षा, नवाचार और भविष्य पर निवेश कर पाता है।यानी सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज मिलकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं।परिवार पर पड़ता तिहरा असर- जब शिक्षा महंगी होती है, इलाज महंगा होता है और कैंसर जैसी बीमारी दस्तक देती है,तो असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता।

(1) परिवार की बचत खत्म होती है (2) बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है (3) मानसिक तनाव पीढ़ियों तक असर डालता है,यही कारण है कि ये मुद्दे केवल सामाजिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रश्न बन जाते हैं। साथियों बात अगर हम नीति- निर्माताओं के सामने स्पष्ट संदेश इसको समझने की करें तो,अब समय आ गया है कि(1) शिक्षा को खर्च नहीं, राष्ट्रीय निवेश माना जाए (2) स्वास्थ्य को दया नहीं, अधिकार समझा जाए (3) कैंसर को बीमारी नहीं बल्कि संयुक्त नीति आपातकाल की तरह देखा जाए। भारत की वास्तविक शक्ति उसके परिवार हैं।

सम्पादकीय...

भविष्य क्या...?

भारत में जेलों में पल रहे नौनिहालों का भविष्य वाकई में गंभीर संकटों से घिरा हुआ है। ऐसे बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व के विकास की संभावना जेल की दीवारों के भीतर लगभग अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उनका बचपन अंधकारमय हो जाता है। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था तब मैंने भी बंदी कल्याणार्थ किरण परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर जेल में कई वर्ष कार्य किया था। जिसके तहत बंदी कल्याण के सभी कार्यों को करने की जिम्मेदारी थी। चाहे वह कानूनी हो पुनर्वास और शिक्षा हो या अन्य मानवीय समस्याओं का समाधान हो। यह बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ परियोजना थी। जिसकी पहल तत्कालीन संभाग आयुक्त उपाध्याय जी द्वारा शुरू की गई थी।

इस परियोजना के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात इस परियोजना को बंद कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर कई हजार बच्चे अपनी माताओं के साथ विभिन्न जेलों में रहते हैं। इनमें से बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसी राज्यों में हैं। ऐसे बच्चों को स्वाभाविक बालपन, उचित शिक्षा और सामाजिक अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। जेल का वातावरण उनके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की भीड़ है, जिसके कारण संसाधन और सुविधाएं पहले से ही सीमित होती हैं। बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य, पोषण और खेलकूद की सुविधा नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक वातावरण और बच्चों के लिए सकारात्मक सामाजिक माहौल की भारी कमी है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और सामाजिक समझ कमजोर पड़ती है ऐसे बच्चे, किशोर किशोरिया जिन्हें बाहरी अभिभावक परिवार या समाज का सहारा नहीं मिलता है वह अतिरिक्त मानसिक दबाव व असुरक्षा के साथ बड़े होते हैं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे निरूद्ध बच्चों के लिए जेल परिसर से बाहर सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, मानसिक परामर्श, स्वास्थ्य और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वहीं कानूनों में संशोधन करके ऐसे मामलों में बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और वह जेल के बजाय संस्थागत देखभाल या परिवार के संरक्षण में रह सकें, साथ ही महिलाओं के लिए खुली जेल या ट्रांजिट होम जैसी व्यवस्थाएं मिल सकें, जहां माँ और बच्चे मानवीय गरिमा के साथ गुजारा कर सकें। सरकार और जेल प्रशासन को बाल अधिकारों की रक्षा और बच्चों के कल्याण के लिए एकरूपता के साथ नीति लागू करने की आवश्यकता है ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो। कई जेलों में बाल संरक्षण नीति के तहत आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा की सुविधाएं शुरू की गई हैं, परन्तु ये पूरे देश में एकसमान लागू नहीं हैं? जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल प्रशासन की देखरेख में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य संवर सके और वे बड़े होकर देश के एक जिम्मेदारी नागरिक की भूमिका निभा सकें। बचपन की नींव पर ही जीवन का भवन टिका होता है; जेलों में पलते बच्चों का वह स्वप्निल भविष्य वर्तमान व्यवस्था की सीमाओं में कैद हो जाता है। इसलिए ऐसे नौनिहालों के लिए विशेष और संवेदनशील नीतियों और व्यवस्थाओं की तत्काल आवश्यकता है, ताकि उनका भविष्य फिर से रोशन हो सके। जेल में निरूद्ध बंदियों के बच्चों का भविष्य संवारने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में जेल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जेल का माहौल बच्चों के लिए सुरक्षित और अनुकूल बनाना, सामाजिक कलंक और बहिष्कार से बचाना, तथा पारिवारिक माहौल की कमी को दूर करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेल प्रशासन को बच्चों के अधिकारों का सम्मान करना होगा और शिक्षा, सुरक्षा और संपूर्ण विकास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिससे जेल में रहते हुए भी इन बच्चों का भविष्य जेल प्रशासन को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा से कट न जाएं और उनका बचपन जेल की सलाखों में कैद न हो। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा महिला बंदियों के बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन योजना जैसी पहल की गई है, जिसमें संरक्षण, शिक्षा और पोषण की जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों की संयुक्त समिति को दी जाती है। यह एक अच्छी पहल है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए।

अरावली को जीवनदान

अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास भारत से भी पुराना है। अरावली पर्वत तब बने थे जब गंगा नदी नहीं थी। हिमालय नहीं था। महाद्वीप आपस में जुड़ रहे थे। जीवन की उत्पत्ति की शुरूआत हो रही थी। 250 करोड़ साल पुरानी और 670 किलोमीटर लंबी यह पर्वत श्रृंखला एक भौगोलिक चमत्कार है। यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। यह दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंची है। यह राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में है। यह भारत की प्राकृतिक हरी दीवार है। जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। बिना अरावली के हरियाणा और दिल्ली भी रेगिस्तान होते। यह मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है और वर्षा बढ़ाती है। अरावली कई नदियों का स्रोत है। यह जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का पानी चट्टानों में रिसता है और भूजल बनाता है। यह एक तरह से प्राकृतिक स्पंज जैसा है जो बारिश का पानी नीचे जमीन में भेजता है। यह एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है जो 300 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों को संरक्षण देता है और वनस्पति का संरक्षक है। इतिहास की बात करें तो अरावली पर्वत माला को राजपूतों की ढाल और मुगलों के लिए काल कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए सुरक्षित स्थान दिया था। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में आई जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में विकास बनाम प्रकृति के संरक्षण को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। जिस देश में पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हों उस समाज में प्रकृति के संरक्षण को लेकर प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। सन् 1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। अंततः राजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था और बिश्नोई गांव के आसपास के पेड़ों को संरक्षित घोषित कर दिया गया था। देशभर में जागरूक समाज और पर्यावरणविदों ने पहाड़ बचाने के लिए आवाज बुलंद की क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर प्राकृतिक का बेलगाम दोहन जारी रहा तो जीवन नहीं बचेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली की पहाड़ियां माना जाएगा। अरावली की नई परिभाषा को लेकर बहुत सारी आशंकाओं ने जन्म ले लिया कि अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन निर्माण और अन्य गतिविधियां जारी रहीं तो इसके गम्भीर पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। लोग सड़कों पर उतरने लगे। सोशल मीडिया पर अरावली बचाओ अभियान ट्रेंड करने लगे। इसके बाद केन्द्र सरकार ने भी पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करते हुए और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर हंटर चला दिया। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है कि अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जलस्तर से कोई समझौता नहीं होगा। पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद खनन माफिया के नए खेल की कोई संभावना नहीं बची है।

सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, मंत्रालय ने 'इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन' को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन' को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आईसीएफआरई एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित 'सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान' (एसएमएमपी) तैयार करेगा। इस प्लान में यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने भी 100 मीटर के नियम पर फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि जब तक नई खनन योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के खिलाफ हरियाणा के रिटायर्ड वन संरक्षक आर.पी.बलवान की याचिका स्वीकार कर ली है। यह मामला पुराने टीएन गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़ा है, जिसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने 'वन' की व्यापक परिभाषा दी थी। नवंबर 2025 में कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को मानते हुए अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की थी इसके तहत स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, साथ ही उनकी ढलान और आसपास की जमीन भी इसी दायरे में आएगी लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी जिससे पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अरावली की सही परिभाषा क्या हो पिछले कुछ दशकों से अवैध खनन माफिया और भू माफिया ने पहाड़ों को निगल लिया है और वहां कंक्रीट की कालोनियां खड़ी कर दी हैं। एक बार खनन का दरवाजा खुला तो अवैध खनन माफिया फिर सक्रिय हो जाएगा।

सुशासन की राह पर अग्रसर हरियाणा

सुशासन-जिसका मूल अर्थ है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक कार्यों और संसाधनों का प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी प्रबंधन। हरियाणा सरकार का मूल मंत्र भी यही रहा है और आज भी बना हुआ है। ई-गवर्नेंस के मार्ग पर चलते हुए बीते ग्यारह वर्षों में हमारी सरकार द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण, समयबद्ध और बाधारहित सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और महान राजनेता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वे भारत में सुशासन के प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। उनका शासन मॉडल वैचारिक प्रतिबद्धताओं और व्यावहारिक, समावेशी तथा जन-केंद्रित प्रशासन के संतुलन से परिपूर्ण था। उनका दृढ़ विश्वास था कि शासन का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाना और विशेष रूप से गरीबों तथा वंचितों का कल्याण सुनिश्चित करना है। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हरियाणा से विशेष लगाव था। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर हरियाणा का दौरा और प्रवास किया। यह बड़े ही संयोग की बात है कि 24 दिसंबर, 1987 के ही दिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए भी पधारे थे। श्री वाजपेयी जी की सोच से प्रेरणा लेते हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, जिसके अनुसार सुशासन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी आवश्यक है तथा ई-गवर्नेंस इसका प्रमुख साधन है। हरियाणा सरकार ने व्यापक नीतियों में सुधार किए हैं। हमारा मानना है कि नीतिगत निर्णय हितधारकों की नब्ज टटोलने के बाद लिए जाते हैं। सार्वजनिक हित की सेवा के लिए कानून के शासन और सहभागिता के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए निर्णय लिए जाते हैं जिससे समान विकास और नागरिकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार जनता की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन को सरल बनाना और उद्योग के लिए कारोबार करना आसान बनाना हमारा लक्ष्य है। भारत को ई-गवर्नेंस के माध्यम से रूपांतरित करने की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने और लोगों तथा कल्याणकारी योजनाओं के बीच की दूरी को शून्य करने के लिए अनेक ई-हस्तक्षेप किए गए हैं जिससे आज हरियाणा में अधिकांश सेवाएं केवल एक क्लिक की दूरी पर हैं। सुशासन सुधारों ने लोगों को उनके घर बैठे या नजदीकी सामुदायिक सेवा केन्द्रों पर जाकर सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। वर्षों से अनसुलझे मामलों को सुलझाने में सक्षम फोरेंसिक व्यवस्था से लेकर एआई-सक्षम आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों तक, महिलाओं की सुरक्षा पहलों से लेकर परिणामोन्मुख साइबर अपराध नियंत्रण तक हरियाणा पुलिस मानवीय दृष्टिकोण के साथ नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग में नए मानक स्थापित कर रही है। हरियाणा का तकनीक-संचालित शासन मॉडल दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म किस प्रकार जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए नागरिकों को सशक्त बना सकते हैं। भूमि और राजस्व अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। करोड़ों पृष्ठों के राजस्व अभिलेखों को स्कैन, सत्यापित और डिजिटाइज करके हरियाणा ने न केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित किया है।

बच्चों को उनका बचपन लौटा दो

पिछले कुछ सप्ताह में कई अलग जगहों से स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या करने के दुखदाई समाचार पढ़ने को मिले हैं। जिस उम्र में बच्चों के खेलने-कूदने के दिन हैं, कुछ मुक्ति पाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल की दसवीं क्लास के 16 वर्षीय लड़के ने एक मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर जान दे दी और यह नोट छोड़ गया, सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोड़ूंगा.। इस एक वाक्य के पीछे बच्चे की कितनी मजबूरी छिपी थी? वह बच्चा क्या-क्या बर्दाश्त करता रहा होगा कि वह आखिरी कदम उठा लिया? क्या कहीं से कोई सहारा नहीं मिला? कोई समझाने वाला नहीं? स्कूल में भी नहीं, और जैसा आजकल नई शिकायत मिल रही है, घर में भी नहीं? यह बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन रही है। आंकड़े बहुत तकलीफदेह हैं। 2023 में नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ने 14,000 स्टूडेंट सुसाइड केस दर्ज किए थे। यह देशभर में कुल सुसाइड का 8.3% है। एक दशक में ऐसे सुसाइड में 65% की वृद्धि हुई थी। यह राष्ट्रीय सुसाइड रेट से अधिक है। हमारे जमाने में तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं जाती थीं। कभी-कभार कोई इश्क के चक्कर में जान दे देता था, पर शिक्षा सम्बंधी या शिक्षा संस्थान सम्बंधी सुसाइड कभी नहीं सुना था। क्या समाज की गति और अपेक्षा, और उपेक्षा, इतनी बढ़ गई है कि जो बच्चे बराबर दौड़ नहीं पा रहे वह निकलने का आसान रास्ता ढूंढने लगे हैं? कोटा के 'शिक्षा-कारखानों' से हर साल कई बच्चों के आत्महत्या करने के कष्टदायक समाचार मिलते हैं। वहां भारी शैक्षणिक दबाव है। अभिभावकों की उम्मीद का दबाव होता है। समाज भी बहुत तेजी से बदल रहा है और केवल श्रेष्ठ को ही सलाम करता है। सब बच्चे तो अव्वल नहीं आ सकते, कई कमजोर टूट जाते हैं। इस सारे मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे ने मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाई वह टीचर्स के हाथों बार-बार अपमानित होने की शिकायत कर गया है। एफआईआर में लिखा गया है कि उसने काउन्सलर को बताया था कि 'वह सुसाइड करने की सोचता है,' पर स्कूल ने परवाह नहीं की और न ही उसके मां-बाप को बताया। जयपुर में नौ वर्ष की बच्ची ने बार-बार उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जिस दिन उसने आत्महत्या की उस दिन 45 मिनट में पांच बार उसने टीचर से शिकायत करने की कोशिश की कि उसके साथ सहपाठी अश्लील मजाक कर रहे हैं, पर टीचर ने कोई परवाह नहीं की। लड़की ने चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। रतलाम में 8वीं क्लास के छात्र ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। वह बच गया, पर यह घटना भी स्कूली उपेक्षा का परिणाम है। स्कूल में मोबाइल लाने पर पाबंदी है, पर यह छात्र ले आया। क्लास का वीडियो बनाकर उसने अपलोड कर दिया। स्कूल ने उसके मां-बाप को बुलाया। बताया जाता है कि लड़के ने 52 बार माफी मांगी पर प्रिंसिपल ने उसका कैरियर तबाह करने की धमकी दे दी। वह स्केटिंग में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। कुछ ही क्षणों बाद उसने छलांग लगा दी। स्कूल में मोबाइल न ले जाने देना बिल्कुल जायज है। हर स्कूल में यह पाबंदी चाहिए, न केवल बच्चों पर बल्कि टीचर्स पर भी। पर जब लड़के ने बार-बार माफी मांग ली तो प्रिंसिपल को भी उदारता दिखाते हुए मामला छोड़ देना चाहिए था। स्कूल का काम बच्चे को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं। ऐसा ही विचलित करने वाला मामला महाराष्ट्र में वसई से है जहां स्कूल देर से आने पर 13 वर्ष की नाजुक लड़की से 100 बैठकें निकलवाई गईं। वह वहीं बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। स्कूल में अनुशासन चाहिए, पर वह क्रूरता की हद तक नहीं जा सकता। वह जमाना गया जब आप बच्चों को मुर्गा बनाने की सजा दे सकते थे। संतुलन रखना अध्यापकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि समाज बदल गया। बहुत बच्चे जिन्हें डिस्टर्ब्ड फैमिली कहते हैं, से आते हैं। एक स्कूल प्रिंसिपल जो कमजोर परिवारों के बच्चों के स्कूल को चलाती है, ने मुझे बताया कि आधे बच्चे 'ब्रोकन फैमिली' अर्थात टूटे परिवार से आते हैं। ऐसे बच्चों को सम्भालना और अधिक चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन इस समस्या का एक और पहलू भी है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, मां-बाप और परिवार की जिम्मेवारी। दिल्ली के जिस लड़के ने मैट्रो स्टेशन से छलांग लगाई थी उसने स्कूल के काउन्सलर को बताया था कि वह सुसाइड करने की सोचता है। मेरा सवाल दूसरा है। स्कूल की लापरवाही तो है ही, पर मां-बाप को क्यों पता नहीं चला कि बच्चा इतना हताश और निराश है कि सुसाइड करने के बारे सोच रहा है? घरों में बच्चों के साथ संवाद क्यों नहीं होता? स्कूल अब बच्चों से संवाद करने और उनकी तकलीफों को बारे जानने के लिए काउन्सलर रखते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब जरूरत क्यों पड़ गई? एक काउन्सलर ने मुझे बताया कि छोटे- छोटे बच्चे भी अपनी बात कहने आते हैं। क्या घर में सुनने वाला कोई नहीं? कई परिवारों में दोनों पति-पत्नी काम करते हैं जिससे बच्चा कटा महसूस करता है। अपनी बात अंदर छिपा कर रखता है जिससे घुटन पैदा होती है जो कई बार यह अप्रिय मोड़ ले लेती है। कई परिवार सारी जिम्मेवारी स्कूल पर डाल कर बैठ जाते हैं। यह सही नहीं है। कई बाप तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। जवाब मिलता है, ⁼टाइम किस्थे है जी!⁼ आजकल के समय जब बच्चों पर बाहरी प्रभाव बहुत बढ़ गया है, अभिभावकों की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है कि वह बच्चे पर निगरानी रखें कि किधर जाता है और किस से बात करता है ? मोबाइल फोन ने तबाही मचा दी है। बहुत विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अत्यधिक सोशल मीडिया सम्पर्क बच्चों के लिए हानिकारक है। बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है। मैटा की अपनी रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया से बच्चों की मानसिक और शैक्षणिक क्षमता पर असर पड़ता है। आस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। आस्ट्रेलिया की अपनी स्टडी बताती है कि 10-15 वर्ष के बच्चों में 10 में से 7 में सोशल मीडिया के प्रभाव हानिकारक पाए गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि ऐसे बच्चों में बोलने और लिखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। उनमें खाने में विकार से लेकर सुसाइड के बारे सोच पाई गई। दूसरे देश भी आस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया होती है? कई बच्चे सदमें में हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों की दिनचर्या में सोशल मीडिया गहराई से जुड़ चुका है। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करेंगे? यह मां-बाप की असफलता है जो बच्चे को बिजी रखने के लिए छोटी उम्र में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चों को आउट डोर गेम्स में व्यस्त रखने की जगह मोबाइल में व्यस्त रखा जाता है। बच्चों में जल्द गुस्सा आना, आंखों में दर्द, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना सब मोबाइल से जुड़े हैं। पढ़ाई में ध्यान कम हो रहा है। डाक्टर बताते हैं कि छोटे बच्चों से माइग्रेन की शिकायत आने लगी है, जो पहले सुना भी नहीं जाता था। भारत में मोबाइल पर कोई पाबंदी नहीं है, पपेरेंट्स को उनके स्क्रीन टाइम पर नजर रखनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है। यह तो सही है, पर जहां मां-बाप बच्चे को इस लत से बचाने में नाकाम हो रहे हैं वहां कुछ सरकारी दखल की जरूरत बनती है, पर केवल मोबाइल ही बच्चों को खराब नहीं करते। ज्योत्सना मोहन भार्गव ने शहरी बच्चों पर लिखी अपनी किताब स्टोड, शेम्ड, डिप्रेस्ड में लिखा है, सड़क पर खतरे के निशान बिखरे पड़े हैं फिर भी मैं शहरी घरों में बेबसी की भावना देखती हूं। जो सामने है उसे नकारा जा रहा है, जिसके कई बार बहुत भयानक परिणाम निकलते हैं। अब तो कई पेरैंट्स गर्व से कहते हैं कि हम अपने बच्चे के 'फ्रैंड' हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। पेरैंट को पेरैंट रहना चाहिए, बच्चे का दोस्त नहीं बनना चाहिए। उनका काम बच्चे को गलत प्रभाव से बचाकर सही दिशा में डालना है। पिछले कुछ सालों में हमारा समाज बहुत हिंसक हो गया है। ड्रग्स का बहुत चलन है और आसानी से मिल जाते हैं। सब 90% से अधिक नम्बर भी नहीं ला सकते। ध्यान रखने की जरूरत है कि इसकी कीमत बच्चा मानसिक या शारीरिक तौर पर न अदा करें, अगर आप का बच्चा डिप्रेस्ड या दुखी है या गलत आदतों में फंस गया है तो स्कूल से पहले घर को पता चलना चाहिए। पश्चिम में बहुत मां-बाप बच्चों पर नियंत्रण खो बैठे हैं। हमें सावधान रहना है। अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के पास मोबाइल नहीं है । अगर उसके फ्रैंड्स ने उससे बात करनी होती है तो उसकी मां के फोन पर सम्पर्क करते हैं। कितने पेरेंट्स के पास यह दम है कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखें ? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया देखने पर पाबंदी लगाने के बाद आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का कहना है कि ⁼हम बच्चों को उनका बचपन लौटा रहे हैं⁼। क्या हमारी सरकार भी बच्चों को डिजिटल प्रदूषण से बचा कर उनका बचपन लौटाने के बारे सोचेगी?

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शेरी ने चन्दन ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सदर पोफलशला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार शेरी, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक

वीर सपूतों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि

मुरादाबाद।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आवाहन पर जिला एवं महानगर के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला के नेतृत्व में दसवें सिख गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों, साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम के अंतर्गत महानगर कार्यालय बुद्धि विहार पर एक संगोष्ठी एवं बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के चरित पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में महानगर प्रभारी मोहन लाल सैनी शामिल रहे। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता मोहन लाल सैनी ने कहा कि वास्तव में भारत की धरती वीरों की धरती है हमारे महापुरुषों से हमें जो संस्कार और संस्कृति मिली है आज का दिन सिख समाज को समर्पित करते हुए आज हम उनको याद करते हैं उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस के अवसर पर हम दसवें सिख गुरु गोविन्द सिंह जी के पुत्रों साहिबजादो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दोनों वीर सपूतों को उनके साहस को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं नमन करते हैं। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि बहुत कम उम्र में भी

उन दोनों वीरों ने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण नौछवर कर दिए। संगोष्ठी के समापन पर जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने कहा कि हमारे वीर सपूतों ने साहबजादो ने जो बलिदान किया वे दोनों छोटे ब'चे अपने धर्म की रक्षा के लिए झुके नहीं और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी हमे उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। संगोष्ठी कार्यक्रम के उपरांत आयोजित की गई प्रदर्शनी को सभी ने देखा और उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करने का संकल्प लिया। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता महानगर प्रभारी मोहन लाल सैनी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल जिला प्रभारी राजेश यादव एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त एम एल सी गोपाल अंजान प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा जसप्रीत सिंह खुराना सचिव तेजिंदर सिंह एवं गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यगण जिला मह्यमंत्री राजन विश्नोई प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जायसवाल महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता कमल प्रजापति हरज्ञान सिंह आचार्य नरेंद्र हुकुम सिंह चकित चौधरी नवीन चौधरी महानगर उपाध्यक्ष नवदीप टंडन राहुल शर्मा दिनेश सिसोदिया हेमराज सैनी शम्मी भटनागर सर्वेश पटेल अभिषेक चौबे आदेश चौधरी सिंपल चौहान सुनीता शर्मा शशी किरण सुनीता सैनी पूर्णिमा खन्ना हेमा खत्री विपिन प्रजापति मिथुन शर्मा विशाल रस्तौगी सोमपाल प्रजापति राजीव शर्मा वीरपाल सिंह कपिल गुप्ता सूर्य मोहन शमशेरी गजेंद्र लोदी अर्चित गुप्ता हरेंद्र शर्मा मुकेश भारद्वाज मनमोहन सैनी आदि महानगर मंडल मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं पार्षदगण शामिल रहे।

कंबल पाकर खुशी से खिल उठे चेहरें

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप के बीच, सरकार और प्रशासन गरीबों की मदद के लिए सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पं महर्षि दयानन्द लॉ कॉलेज भदासना और लीलावती भगवतशरण स्कूल रतनपुर कलां में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। यह पहल बढ़ती ठंड से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी दिखी। तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों से आए पात्र लाभार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ठंड में असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। शासन की मंशा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। विधायक ने आगे कहा कि जनसेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। गरीब और असहाय लोगों की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है। विधायक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि क्षेत्र में कोई भी पात्र व्यक्ति इस सुविधा से वंचित न रहे। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमे ब्लॉक प्रमुख गुलाम जिलानी, तहसीलदार अंकित गिरी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सैनी, नीरज चंद्रा, बबलू जाटव, अशोक तोमर, रोहित सिंह, जय सिंह, मयंक शर्मा, विजयपाल सैनी, बलजीत जाटव आदि उपस्थित रहे।

प्रत्येक विद्यालय में सुनिश्चित रहे फर्नीचर की उपलब्धता: डीएम

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में ब'चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित कराई जाए इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए की ग्राम पंचायत के माध्यम से बेंच का प्रबंध कराया जाए तथा उपलब्धता की स्थिति की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि ठंड के दौरान ब'चों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय की सप्ताह में कम से कम एक बार बेहतर तरीके से साफ सफाई व्यवस्था भी कराई जाए जिसमें विद्यालय परिसर के आसपास झाड़ियों की कटाई हो। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में जिन सफाई कर्मियों द्वारा विद्यालय परिसर की साफ सफाई करने में रुचि नहीं

ली जा रही है अथवा लापरवाही बरती जा रही है उनकी सूची भी तैयार कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में फूलों की पौध लगाए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए थे इसका अनुपालन होना चाहिए ताकि विद्यालयों में बच्चों के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल हो सके। ब'चों की ड्रेस, जूते, मोजे आदि की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 01 जनवरी 2026 से पूर्व प्रत्येक विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले ब'चों को विभिन्न गतिविधियों एवं प्री शिक्षा से जोड़ने के लिए निर्धारित पहल पुस्तिकाओं के वितरण की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी ने आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा कहा कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहल पुस्तिका का वितरण नहीं किया गया है। वहां प्राथमिकता के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी उन

बेसिक शिक्षा के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न

ससाधनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते रहें। विद्यालयों में तैयार होने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के बारे में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विद्यालयों में बर्तन पुराने हो गए हैं वहां नए बर्तनों की खरीद कर ली जाए। शहरी क्षेत्र में संचालित परिषदीय विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन की उपलब्धता नहीं होगी, जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन की उपलब्धता कराई जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी, जिला विकास अधिकारी जीवी पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार और जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।

पुलिस घुड़सवारों ने दिखाये करतब

मुरादाबाद।

डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में शुक्रवार से चार दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन डीआईजी मुनिराज ने किया। इसमें प्रदेश के छह जनपदों की पुलिस घुड़सवार टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान 37 घोड़े विभिन्न स्पर्धाओं में अपना कौशल दिखा रहे हैं। 14 अलग-अलग स्पर्धाओं में घुड़सवारों की दक्षता, नियंत्रण और तालमेल की परीक्षा ली जा रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमें अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए चयनित होंगी। इस दौरान प्रतियोगिता के टेंट पेगिंग इवेंट में दौड़ते समय मुरादाबाद टीम का घोड़ा बादल अचानक मोच आने से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद पशु चिकित्सकों और अधिकारियों ने तत्काल घोड़े का उपचार कराया। फिलहाल घोड़ा चिकित्सकीय निगरानी में है। उद्घाटन के मौके पर डीआईजी पुलिस अकादमी विकास कुमार वैद समेत अन्य पुलिस अफसर एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।

टीएमयू में एरिदमिया का रंगारंग आगाज़

मुरादाबाद।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण-एमडीए के वीसी अनुभव सिंह ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के एरिदमिया की भव्यता एवम् विविधता की मुक्तकंठ प्रशंसा करते हुए कहा, उन्हें अपने कॉलेज टाइम की यादें ताज़ा हो गई हैं। उन्होने मेडिकल के छात्रों के संग अपने कॉलेज जीवन के यादगार अनुभव और किस्से भी साझा किए। उपाध्यक्ष श्री सिंह तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित सात दिनी स्पोर्ट्स, क्लचरल एंड टैलेंट इवेंट- एरिदमिया 2025 के शंखनाद मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्य अतिथि ने चित्रकला प्रदर्शनी का विशेष रूप से अवलोकन किया और मेडिकल स्टुडेंट्स की कलात्मक प्रतिभा की सराहना की। इससे पूर्व बतौर मुख्य अतिथि अनुभव सिंह, कुलाधिपति सुरेश जैन,डायरेक्टर प्रशासन अभिषेक कपूर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. एनके सिंह आदि ने रंग बिरंगी रोशनी के बीच मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र'जवलन, मशाल जलाकर और गुब्बारे उड़ाकर रिद्धि-सिद्धि भवन में एरिदमिया का रंगारंग आगाज़ किया।

दूसरी ओर रात को मेडिकल स्टुडेंट्स को ऑडी में बॉलीवुड फिल्म दे दना दन दिखाई गई। एरिदमिया के शंखनाद के मौके पर मेडिकल साइंसेज के डीन प्रो. एसके जैन, वाइस प्रिंसिपल प्रो. प्रीथपाल सिंह मटरेजा, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रो. आरके द्विवेदी, पैथोलॉजी की एचओडी एवम् अरिदमिया- 2025 की

सात दिनी स्पोर्ट्स, क्लचरल एंड टैलेंट इवेंट में एमडीए के वीसीअनुभव सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

कन्वीनर प्रो. सीमा अवस्थी के संग-संग इवेंट्स कॉर्डिनेटर्स आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। उल्लेखनीय है, एरिदमिया में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के तहत क्रिकेट, फुटबाल, बास्केटबाल, वालीबाल, थ्रोबाल, बॉक्स क्रिकेट, टग ऑफ वार, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन, ट्रैक एंड फील्ड, टेबिल-टेनिस, स्कैश, आर्म रेसलिंग, पुश-अप्स, कैरम, चेस आदि, कल्चर इवेंट के तहत गिफ्ट वार्पिंग, ग्लास पेंटिंग, आर्ट एग्जिबेशन, डिबेट, ट्रेजर हंट, पिक्शनरी, कॉमेडी स्किट, कॉमिक बुक मेकिंग, मीम मेकिंग, एड मेकिंग, रील मेकिंग, शिल्पकारी, फोटोग्राफी, जबकि इवनिंग एंड नाइट इवेंट में सोलो डांस, डुएट डांस, ग्रुप डांस, सोलो सिंगिंग, डुएट सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, टैलेंट हंट, फैशन शो आदि में भावी डॉक्टर्स अपने हुनर का जलवा दिखाएंगे।

नव वर्ष के स्वागत में सजी साहित्य की महफिल

मुरादाबाद। साहित्यिक समाज द्वारा आज नव वर्ष स्वागत एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के 101 वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काव्य गोष्ठी एवम व्याख्यान का आयोजन किया। सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के सम्मुख मुख्य अतिथि जकार्ता इंडोनेशिया से पधारी साहित्यकार वैशाली रस्तोगी ने दीप प्र-वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोपाल हरि गुप्ता के निवास पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य पीडिया की संस्थापक डॉ. अर्चना गुप्ता ने और संचालन भारत विख्यात रामलीला निर्देशक डॉ. पंकज दर्पण अग्रवाल ने किया। इसके बाद काव्य पाठ का सिलसिला आरम्भ हुआ। युवा कवि दुष्यंत बाबा ने अपनी कविता में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कि अवस्था को प्रदर्शित किया। बहुत तेजी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने वाले कवि मयंक शर्मा ने अटल बिहारी बाजपेई जी को समर्पित देशभक्ति गीत को सुनाया। डॉ0 रीता सिंह ने प्रकृति पर तो डॉ. अर्चना गुप्ता ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर पर हाल ही में स्थापित धर्म ध्वजा के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया। वैशाली रस्तोगी के दोहे, घनाक्षरी और गीत ने कार्यक्रम को शिखर पर ही पहुंचा दिया। काव्य गोष्ठी में श्री कृष्ण शुक्ल व मंजु गुप्ता ने भी काव्यपाठ किया। डॉ. पंकज दर्पण अग्रवाल एवम धवल दीक्षित ने अपने विचार रखे। आभार अभिव्यक्ति गोपाल हरि गुप्ता ने की। कार्यक्रम के अंत में इंडोनेशिया में रहकर भारतीय संस्कृति एवम साहित्य के प्रसार में संलग्न वैशाली रस्तोगी को शॉल ओढ़ाकर सम्मान पत्र एवम सम्मान चिन्ह भेंट किये गए। सभी साहित्यकारों का भी अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया गया।

लालकिला बम विस्फोट और वायु प्रदूषण से बचने की चुनौती, दिल्ली के लिए कैसा रहा 2025 का साल

नई दिल्ली । 2025 का साल दिल्ली के लिए कई मायनों में ऐतिहास रचने वाला रहा है। एक समय वैकल्पिक राजनीति के प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल को इसी साल के फरवरी में दिल्ली में हुए चुनावों में करारी हार हुई। शराब घोटाले में जेल गए और अपने सरकारी आवास पर भारी पैसा खर्च कर विवादों में घिरे केजरीवाल स्वयं अपनी सीट नहीं बचा सके। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकी और उसने दिल्ली में चुनियादी बदलाव करने का वादा किया है। साल बीतते-बीतते दिल्ली को लालकिले बम विस्फोट ने आहत कर दिया। दिल्ली की सरकार और प्रशासन के सामने इस बात की बड़ी चुनौती रहेगी कि वह दिल्ली को आतंकी खतरों से कैसे सुरक्षित रखती है।

अरविंद केजरीवाल की हार, भाजपा की प्रचंड जीत

वर्ष 2025 दिल्ली की स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव पैदा करने वाला साल रहा। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी सरकार की करारी हार हुई। शराब घोटाले में कई महीने जेल के अंदर रहे अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई और वे अपनी सीट तक हार गए। सरकार में नंबर दो रहे मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा सके। केजरीवाल की हार का अर्थ केवल एक राजनीतिक दल की एक चुनाव में हार तक सीमित नहीं है। उनकी हार ने आम आदमी पार्टी की भविष्य की राजनीतिक यात्रा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल की हार के बाद दिल्ली में भाजपा ने 27 साल बाद सरकार बनाने में सफलता हासिल की। पार्टी ने एक महिला रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाते हुए महिला मतदाताओं को विशेष संदेश दिया।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना में 18 की मौत

भीड़ प्रबंधन न कर पाने के कारण दिल्ली में अनेक बार बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं में अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2025 भी इस मामले में अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के लिए 16 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे। भीड़ का सही प्रबंधन न कर पाने के कारण भगदड़ मची और इसमें 18 लोगों की दुखद मौत हो गई।

दिल्ली के सामने चुनौती- वायु प्रदूषण से बचाव

वायु प्रदूषण केंद्र और दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इस वर्ष वायु प्रदूषण का स्तर 500-600 अंक को पार करता रहा है। 400 पार एक्यूआई वाले दिनों की संख्या लगातार बढ़ती रही है।

वायु प्रदूषण पर रोक लगाम न लगा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई भी की है। आने वाले समय में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्थाई उपाय कर पाना रेखा गुप्ता सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।

हताशा का दौर खत्म, जेन-जी के लिए अवसरों की भरमार, पीएम मोदी ने युवाओं को किया सशक्त

नई दिल्ली ।

विभिन्न क्षेत्रों में पैदा हो रहे अवसरों की प्रचुरता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जेन-जी की क्षमताओं और आत्मविश्वास पर भरोसा जताया और उन्हें कड़ी मेहनत और अनुशासन के माध्यम से राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने युवाओं को उम्र की परवाह किए बिना बड़ी चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन-जेड, जेन-अल्फा हैं। आपकी पीढ़ी भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जेन-जेड की क्षमताओं

वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने युवाओं को उम्र की परवाह किए बिना बड़ी चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी।

और आपके आत्मविश्वास को देखता और समझता हूं, इसलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उम्र यह तय नहीं करती कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। आप अपने कर्मों और उपलब्धियों से बड़े बनते हैं। कम उम्र में भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दूसरे प्रेरणा लें। पीएम मोदी ने युवाओं को अल्पकालिक लोकप्रियता से विचलित न होने की सलाह दी और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महान व्यक्तित्वों से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आपको एकाग्र रहना होगा, और इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अल्पकालिक लोकप्रियता की चकाचौंध में न उलझें। आपको अपने आदर्शों से सीखना चाहिए, देश के महान व्यक्तित्वों से सीखना चाहिए। आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं समझना चाहिए। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी सफलता राष्ट्र की सफलता बने। यह देखते हुए कि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत को रूपांतरित करने वाली पहलों के माध्यम से निराशा और हताशा के माहौल को पार कर लिया है, पीएम मोदी ने कहा कि अब युवाओं के पास हर क्षेत्र में प्रगति करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पहले, युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्था ने ऐसा माहौल बना दिया था जहां लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर जगह निराशा और हताशा का माहौल छाया हुआ था। लोग सोचने लगे थे, मेहनत करने का क्या फायदा? लेकिन आज, देश प्रतिभाओं की तलाश करता है और उन्हें एक मंच प्रदान करता है। 1.4 अरब देशवासियों की ताकत उनके सपनों के पीछे है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता के बदौलत आपके पास इंटरनेट की शक्ति है। आपके पास सीखने के संसाधन हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान हैं। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए खेलो इंडिया अभियान है। वीर साहिबजादों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने युवाओं को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने न देने के लिए प्रोत्साहित किया।

22 राज्यों में तेज सर्दी-कोहरा, यूपी में जीरो विजिबिलिटी-50+ ट्रेनें लेट

माउंट आबू में पारा 1°, पचमढ़ी में 3.6°; अगले 2 दिन में सर्दी और बढ़ेगी

नई दिल्ली । देशभर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी-एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो हो गई। सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं गोरखपुर समेत कई एयरपोर्ट्स पर 5 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। इधर, मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10° सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। माउंट आबू में पारा 1.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में 1.6 और नागौर में 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

27 दिसंबर- कोहरे का दायरा और फैलेगा, दिन में भी रहेगी धुंध

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर जारी रहेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं।

28 दिसंबर- ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी, रातें ज्यादा सर्द

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कोहरे के साथ ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। कोल्ड-डे जैसी स्थिति रहेगी। कोल्ड डे एक मौसम संबंधी स्थिति है जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10°C से कम हो, और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5°C से 6.4°C तक कम हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं।

लंबी माथापची के बाद बीएमसी सीट बंटवारे पर मुहर! भाजपा 140 और शिंदे सेना 87 पर राजी

मुंबई । कई दिनों की विचार-विमर्श के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए सीट बंटवारे का समझौता कर लिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि महायुति गठबंधन द्वारा तय किए गए फार्मूले के अनुसार, भाजपा 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे की सेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएमसी के लिए मतदान 15 जनवरी को शेष के अन्य सभी नगर निगमों के साथ होगा। वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। यह घटनाक्रम गठबंधन के दोनों सहयोगी दलों के बीच असंतोष की खबरों के बीच हुई मैराथन बैठकों के कुछ दिनों बाद सामने आया है। हालांकि, भाजपा और शिंदे सेना ने इन खबरों को खारिज करते हुए सूत्रों के हवाले से कहा है कि उन्होंने 200 सीटों के लिए सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है और शेष 27 सीटों के लिए बातचीत जारी है। असंतोष की खबरों के बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले शिवसेना का समर्थन किया था और भाजपा नेताओं को शिंदे की पार्टी पर खुलेआम हमला करने से बचने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि भाजपा और शिवसेना एकजुट हैं और उन्हें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दिन में पहले कहा, भाजपा और शिवसेना एकजुट हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हमें औपचारिक रूप से गठबंधन की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति दल का दबदबा रहा, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी शामिल है। इन चुनावों के लिए मतदान दो चरणों में, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को हुआ था, और परिणाम महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा घोषित किए गए। भाजपा ने नगर अध्यक्षों के 117 पद जीते, जबकि शिवसेना ने 53 पद जीते। एनसीपी ने 37, कांग्रेस ने 28, शिवसेना (यूबीटी) ने नौ और एनसीपी (एसपी) ने सात पद जीते। एसईसी के अनुसार, पांच सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने और 28 सीटें गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टियों ने जीतीं।

भारत के माहौल को जानबूझकर दूषित किया जा रहा है- अभिषेक बनर्जी

बंगाल । अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को क्रिसमस पर ईसाइयों पर हुए लक्षित हमलों के बाद दक्षिणपंथी उग्रवाद में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को घेरा। एक्स पर एक पोस्ट में, अभिषेक बनर्जी ने 2002 के एक वीडियो को साझा किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि जनता का प्रतिनिधि लोगों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात दंगों के बाद आयोजित की गई थी। बनर्जी ने दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया और केंद्र पर भारत के माहौल को जानबूझकर दूषित करने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत के माहौल को जानबूझकर दूषित किया जा रहा है। सत्ता से उत्साहित दक्षिणपंथी ताकतें धर्म की आड़ में दलितों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर खुलेआम हमला कर रही हैं - भय, लिंचिंग, धमकियों और नफरत के जरिए। उन्होंने आगे कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग ही हिंसा के अपराधी हों और हिंसा के संरक्षकों को पुरस्कृत करें, तो दंडमुक्ति नीति बन जाती है। यह शासन नहीं, नैतिक पतन है। बनर्जी ने यह भी कहा कि ये हमले असंवैधानिक, अवैध हैं और देश की धर्मनिरपेक्ष नींव को चटका देते हैं। उन्होंने कहा कि वे हमले असंवैधानिक, अवैध हैं और भारत की नींव - हमारी विविधता में एकता - को चकनाचूर कर देते हैं। आज चुप्पी साधना मिलीभगत है। इतिहास इसे माफ नहीं करेगा। अभिषेक बनर्जी की ये टिप्पणियां क्रिसमस समारोह के दौरान देश भर में दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा कथित तोड़फोड़ और हमलों की विभिन्न घटनाओं के बाद आईं। इस बीच, असम में पुलिस ने क्रिसमस समारोह से पहले सेंट मैरी हाईस्कूल की संपत्ति में तोड़फोड़ करने के आरोप में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भास्कर डे, खोति पडगिरी, बिजू दत्ता और नयन तालुकदार के रूप में पहचाने गए इन उपद्रवियों को घटना के बाद असम पुलिस ने गिरफ्तार किया।

वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को नमन

सीएम योगी ने कहा- उनका बलिदान राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा

लखनऊ । वीर बाल दिवस (साहिबजादा दिवस) के अवसर पर पूरे देश में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का आगमन हुआ और कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चार साहिबजादों की शहादत अदम्य साहस, धर्मनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है। उनका बलिदान युगों-युगों तक देशवासियों को कर्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अंतर्गत भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कीर्तन समागम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की और गुरुवाणी के माध्यम से साहिबजादों के बलिदान को स्मरण किया। उधर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साहिबजादों का अद्वितीय साहस, अटूट आस्था और अन्याय के विरुद्ध अडिग संकल्प मानव इतिहास में वीरता और त्याग का अमर प्रतीक है। उनका जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सत्य, धर्म और राष्ट्ररक्षा के मार्ग पर निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

हम नजरअंदाज नहीं कर सकते..., बांग्लादेश में हिंदू युवकों की लिंचिंग पर भड़का भारत

नई दिल्ली । बांग्लादेश में जारी सियासी संकट और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (26 दिसंबर 2025) को कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा चिंता का विषय है. उन्होंने कहा, हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं. हम आशा करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे घटनाएं सामने आई है, जो हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने से संबंधित हैं. इन खबरों को राजनीतिक हिंसा कह कर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता. बांग्लादेश में फरवरी 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सक्रिय हो गई है और जोरों शोरों माहौल बनाने में जुट गई है. इसी सिलसिले में BNP के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका पहुंचे. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार रहमान ने एयरपोर्ट पर पहुंचने के तुरंत बाद नंगे पैर बांग्लादेशी धरती पर खड़े होकर देश की राजनीति में अपनी वापसी को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित किया. तारिक रहमान की वापसी और बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव हो. भारत बांग्लादेश के नागरिकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम वहां शांति और स्थिरता की उम्मीद करते हैं. हर पक्ष के लोग वहां भाग लें और वहां लोगों की आवाज और बुलंद हो. बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म ढाने लगे. भीड़ ने पहले हिंदू युवक दीपू दास की हत्या कर शव को पेड़ से टांगकर जला दिया. इसके बाद राजबाड़ी में अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के युवक को भी भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. इसे लेकर भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में जहां छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाया गया, वहां पहुंच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टेका माथा

नैतिक दृढ़ता, आत्मसम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को किया नमन

चंडीगढ़ ।

इतिहास के सबसे करुण और प्रेरक अध्यायों में दर्ज साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को स्मरण करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब पहुँचे। यह वही पावन धरती है जहाँ धर्म, सत्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों–बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने अल्पायु में ही सर्वोच्च बलिदान दिया।

वीर बाल दिवस छोटे साहिबजादों को स्मरण करने और भावी पीढ़ियों को उनके जीवन से प्रेरणा देने का महान दिवस है। मुख्यमंत्री ने उस ऐतिहासिक स्थल पर माथा टेका, जहाँ अत्याचार के सामने झुकने से इनकार करने पर साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था। मुख्यमंत्री ने नतमस्तक होकर बाल्यावस्था में ही प्रदर्शित की गई उस नैतिक दृढ़ता और आस्था को नमन किया, जिसने सम्पूर्ण मानवता को साहस और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। धर्म, आस्था व मानवता की सेवा का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री स्वयं गुरुद्वारा परिसर में सेवा भी की। गुरुद्वारा परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच यह क्षण स्मरण कराता रहा कि वीरता केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि सत्य और विश्वास पर अडिग रहने में भी निहित होती है। साहिबजादों का बलिदान आज भी समाज को यह संदेश देता है कि उम्र नहीं, बल्कि संकल्प ही इतिहास रचता है। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की यह श्रद्धांजलि उस सामूहिक चेतना को पुनः जागृत करती है, जो नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक साहस और मानवीय गरिमा से जोड़ने का कार्य करती है।

गुरुद्वारा शहीद बाबा मोतीराम मेहरा में भी की अरदास

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा शहीद बाबा मोतीराम मेहरा में पहुंचे और वहां माथा टेका और अरदास की। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबज़ादों–बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी–को सरहिंद के नवाब द्वारा ठंडे बुर्ज में कैद रखा गया था। ऐसे समय में बाबा मोतीराम मेहरा ने मानवता की आवाज़ को अपने अंतःकरण में सर्वोपरि रखा। कठोर प्रतिबंधों और मृत्यु के भय के बावजूद, बाबा मोतीराम मेहरा ने साहिबजादों को दूध की सेवा की।

मुख्यमंत्री ने बाबा मोतीराम मेहरा के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह बलिदान केवल सिख इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश है–कि सत्य और करुणा की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। आज गुरुद्वारा शहीद बाबा मोतीराम मेहरा श्रद्धा और सम्मान का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु उस निस्वार्थ सेवा को नमन करता है, जिसने यह सिखाया कि सच्चा धर्म दूसरों के दुख में सहभागी होना है। यह स्थल याद दिलाता है कि साहस तलवार से नहीं, बल्कि करुणा से जन्म लेता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका

पंजाब । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका, जहां तीन दिवसीय शहीदी सभा का आयोजन हो रहा है। यह वार्षिक समागम 25 से 27 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह आयोजन दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों साहिबज़ादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह तथा उनकी दादी माता गुजरी की स्मृति में किया जाता है। मान ने अपनी पत्नी के साथ 'छोटे साहिबज़ादों' और माता गुजरी के अद्वितीय शहादत को नमन किया। पत्रकारों से बातचीत में मान ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के दोनों छोटे पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को प्रार्थना करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मान ने बताया कि श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा साहिब तक लाने-ले जाने के लिए ई-रिक्शा और शटल बस सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है।